

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र०
(राज्यपाल सूचना परिसर)

15 राष्ट्रों में तैनात भारतीय राजदूतों की राज्यपाल के साथ बैठक सम्पन्न

विभिन्न देशों में स्थापित विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक आदान—प्रदान के सार्थक प्रयास किये जाये

विद्यार्थियों को नौकरी के साथ—साथ स्टार्ट—अप के लिए प्रेरित करें

क्षेत्रीय भाषाओं में भी शोध कार्य किये जायें

कुशल प्रशिक्षित युवाओं की विदेशों में है मांग

—श्रीमती आनंदीबेन पटेल

राजदूतों ने अपने—अपने देश की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में अपने विचार साझा किये

लखनऊ 18 अक्टूबर, 2022

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में 15 देशों में तैनात भारतीय राजदूतों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के 11 कुलपतियों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न देशों में स्थापित विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक आदान—प्रदान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। इस अवसर पर राज्यपाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विगत 3 वर्ष से राज्य विश्वविद्यालयों के नैक ग्रेडेशन तथा नयी शिक्षा नीति लागू करने के लिये बृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम विद्यार्थियों को नौकरी के साथ—साथ स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित करें। स्टार्टअप के माध्यम से यदि विद्यार्थी स्वरोजगार करता है तो वह अपने साथ—साथ अन्य कई लोगों को भी रोजगार दे सकता है। इसलिए हमें विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रेरित करने का कार्य करना है, ताकि आज के युवा आत्मनिर्भर होकर कार्य कर सकें।

राज्यपाल जी ने कहा कि विश्वविद्यालय का दायित्व है कि केंद्रीय से प्रींडीय तक शैक्षणिक वातावरण बनायें तथा विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर गांव, ग्रामीण व किसान तक अपने विद्यार्थियों के माध्यम से पहुंचकर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें। गांव गोद लेकर उन्हें योजनाओं से आच्छादित करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे टींडीय मुक्त हो, 100 प्रतिशत डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, कुपोषण दूर करने के प्रयास करें। ऐसा करने से विश्वविद्यालय के बच्चों में पढ़ाई के साथ सेवाभाव की भावना विकसित होगी।

कुलाधिपति ने बताया कि जब नैक के लिए मूल्यांकन होता है, तो वहां शोध कार्य अंग्रेजी में ही मान्य होता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। क्षेत्रीय भाषाओं में भी शोध कार्य करने के प्रयास किये जाने चाहिए। हमें किसानों की समस्याओं पर भी शोध और उनके निराकरण पर गहनता से विचार करना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यूरिया खाद का दुरुपयोग कर नकली दूध का व्यापार होता था, उसे रोकने के लिये नीम कोटेड यूरिया का निर्माण हुआ फलस्वरूप नकली दूध के व्यापार पर अंकुश लग गया।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उपस्थित सभी राजदूतों तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपील की कि वे देशों के मध्य शैक्षणिक वातावरण तैयार करने हेतु, रिसर्च पब्लिकेशन, भाषायी शिक्षा, रिसर्च का आदान-प्रदान, विद्यार्थियों का आदान-प्रदान, संयुक्त कोर्स, स्टार्ट-अप, बेस्ट प्रैविट्स, सूचना तकनीक रिसर्च, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, आनलाइन तथा आफलाइन शिक्षा, गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों, छात्रों तथा फैकल्टी का आदान-प्रदान, विदेशी छात्रों को प्रोत्साहन, जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर अपने देश की मांग के अनुसार इन क्षेत्रों में आगे बढ़ें। राज्यपाल जी ने कहा कि यदि हम सच्चे मन से इस दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चय ही इसके सार्थक परिणाम सामने आयेंगे।

इस अवसर पर विभिन्न देशों के राजदूतों ने अपने-अपने देश की शैक्षिक जरूरतों और विशेषताओं के बारे में अपने विचार साझा किये। इस क्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उन्नयन हेतु किये जा रहे प्रयासों को बताया तथा अन्य

देशों के साथ शिक्षा एवं तकनीकी के आदान-प्रदान की सम्भावनाओं पर भी व्यापक विचार-विमर्श किया।

इस अवसर पर राज्यपाल जी ने विभिन्न देशों के राजदूतों को 'एक जनपद-एक उत्पाद' के अन्तर्गत निर्मित उत्पाद भेंट किया।

कार्यक्रम में आयरलैण्ड, लाओस, जेनेवा, पोलैण्ड, जार्डन, मैक्सिको, नेपाल, भूटान, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान, थाईलैण्ड, क्रोएशिया, बहरीन, बोत्सवाना तथा साउथ कोरिया के राजदूत, एम०एस०एम०ई० के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल श्रीमती कल्पना अवस्थी तथा 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित राजभवन के अधिकारियों ने भाग लिया।

राम मनोहर त्रिपाठी/राजभवन

9453005360

चन्द्रविजय वर्मा—सूचना अधिकारी

9044381834

